SUSHANT UNIVERSITY ORGANIZED INTERNATIONAL CONFERENCE ON
"ADVANCES IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNVOATION" ICAMRI-2023
ON 28-29TH OCTOBER 2023
INTERNATIONAL ADVANCE JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMENT (IAJESM)
July-December 2023, Submitted in October 2023, iajesm2014@gmail.com, ISSN -2393-8048
Multidisciplinary Indexed/Peer Reviewed Journal. SJIF Impact Factor 2023 =6.753

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारतीय राजनीति में बदलती संस्कृति

डॉ राजकुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा

सार

भारतीय राजनीति में संस्कृति का एक जटिल और गतिशील संबंध रहा है, और उत्तर प्रदेश (यूपी) इस क्रिया का एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म जगत प्रस्तुत करता है। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के रूप में, यूपी की राजनीतिक प्रवृत्तियां अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलावों को दर्शाती हैं। हाल के दशकों में, यूपी के संदर्भ में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव आया है, जो पारंपरिक जाति और धर्म-आधारित पहचान से हटकर विकास, आकांक्षा और एक मजबूत 'हिंदुत्व' पहचान के उदय की ओर बढ़ रहा है। पारंपरिक रूप से, उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म के इर्द-गिर्द घूमती रही है। राजनीतिक दल अक्सर विभिन्न जाति समूहों, जैसे दलितों, यादवों, ब्राह्मणों और ठाकुरों को लक्षित करते हुए, उनकी विशिष्ट मांगों और शिकायतों को पूरा करते थे। धार्मिक पहचान, विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच, भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चुनावी रणनीतियों का एक हिस्सा होता था। यह "पहचान की राजनीति" अक्सर विकास और शासन के मुद्दों पर हावी रहती थी, और मतदाताओं का ध्यान उनकी जाति या धर्म के आधार पर विभाजित होता था। हिंदुत्व, जिसे अक्सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित किया जाता है, केवल एक धार्मिक पहचान से कहीं अधिक है; यह एक राजनीतिक विचारधारा है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है, चुनावी परिणामों को आकार दिया है, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया है और सामाजिक विमर्श को नया रूप दिया है।

मुख्य शब्द: भारतीय, राजनीति, संस्कृति,सामाजिक

भूमिका

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी राजनीति को अक्सर जाति और धर्म के जटिल ताने-बाने से बुना हुआ देखा जाता है। यह सिर्फ चुनावी समीकरणों का खेल नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आर्थिक असमानताओं का भी प्रतिबिंब है। दशकों से, इन दो कारकों ने राज्य की राजनीतिक दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सरकारों का गठन, नीतियों का निर्माण और यहां तक कि सामाजिक सद्भाव भी प्रभावित हुआ है।

पिछले एक दशक में, विशेष रूप से 2014 के बाद से, यूपी की राजनीति में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। विकास और आकांक्षा की अवधारणाएं अधिक प्रमुख हो गई हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने "सबका साथ, सबका विकास" (सभी का साथ, सभी का विकास) के नारे के साथ मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। यह रणनीति, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सुधारों और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया गया, ने पारंपरिक पहचान-आधारित अपील की तुलना में अधिक व्यापक अपील पाई। युवा मतदाताओं और शहरी आबादी के बीच, जो पारंपरिक जातिगत बंधनों से कम बंधे हुए हैं, विकास की यह कथा विशेष रूप से प्रतिध्वनित हुई है।

इस बदलाव के साथ ही, "हिंदुत्व" की अवधारणा भी भारतीय राजनीति में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, अधिक शक्तिशाली रूप से उभरी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जिसे भाजपा ने अपने राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखा था, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीक बन गया है। यह केवल एक धार्मिक स्थल के निर्माण से कहीं अधिक है; यह एक मजबूत हिंदू पहचान और गौरव की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह हिंदुत्व की राजनीति, हालांकि धर्म-आधारित है, पारंपरिक जातिगत विभाजनों को पार करने की कोशिश करती है और एक एकीकृत हिंदू पहचान बनाने का प्रयास करती है। इसने विभिन्न जाति समूहों के हिंदुओं को एक साझा सांस्कृतिक पहचान के तहत एकजुट करने में मदद की है।

इस बदलती संस्कृति के कई निहितार्थ हैं। एक ओर, विकास पर जोर और सुशासन की मांग मतदाताओं के लिए सकारात्मक हो सकती है, जिससे अधिक जवाबदेह और प्रदर्शन-उन्मुख राजनीति हो सकती है। यह जाति और धर्म के आधार पर संकीर्ण राजनीतिक गणनाओं से दूर हटकर एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है। दूसरी ओर, हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव से अल्पसंख्यकों के बीच चिंताएं बढ़ सकती हैं और समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। समावेशी विकास सुनिश्चित करना और सभी समुदायों की चिंताओं को दूर करना इस बदलती सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया और डिजिटल संचार ने इस सांस्कृतिक बदलाव को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक दल अब सीधे मतदाताओं तक पहुंचने के लिए इन प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहे हैं, अपने संदेशों को आकार दे रहे हैं और सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित कर रहे हैं। इसने पारंपरिक मीडिया और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका को बदल दिया है।

जाति, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अकाट्य सत्य है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज विभिन्न जातियों में विभाजित रहा है, और उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा है। दलित (अनुसूचित जातियां), अन्य पिछड़ा

INTERNATIONAL ADVANCE JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMENT (IAJESM)
July-December 2023, Submitted in October 2023, iajesm2014@gmail.com, ISSN -2393-8048
Multidisciplinary Indexed/Peer Reviewed Journal. SJIF Impact Factor 2023 =6.753

वर्ग (ओबीसी), और उच्च जातियां (ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया आदि) सभी अपने-अपने जातीय पहचान और हितों के आधार पर संगठित होते हैं। मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने दलितों को लामबंद करके सत्ता हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) ने यादवों और मुसलमानों के एक बड़े हिस्से के समर्थन से अपनी पहचान बनाई। उच्च जातियां पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़ी रही हैं, हालांकि अब भाजपा ने गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलितों को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है।

चुनावी रणनीतियां अक्सर जातीय अंकगणित पर आधारित होती हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते समय जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखते हैं, ताकि वे अधिकतम मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकें। जातीय रैलियां, जातीय नेताओं का महिमामंडन, और विभिन्न जातियों के लिए विशेष वादे चुनावी परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। हालांकि, यह भी सच है कि जाति आधारित राजनीति ने कभी-कभी समाज में विभाजन को बढ़ावा दिया है और विकास के मुद्दों को पीछे धकेल दिया है।

साहित्य की समीक्षा

धर्म, विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम पहचान, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और शक्तिशाली शक्ति है। राज्य में एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी है, जो अक्सर चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है। राम जन्मभूमि आंदोलन ने राज्य की राजनीति को ध्रुवीकृत किया और भाजपा के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक ध्रुवीकरण ने कई बार सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है, जिसका राजनीतिक दल अक्सर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। [1]

भाजपा ने हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, और राम मंदिर का निर्माण उसके एजेंडे का एक प्रमुख बिंदु रहा है। यह रणनीति हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में सफल रही है, विशेषकर उन लोगों को जो जातीय आधार पर विभाजित हो सकते हैं। मुस्लिम मतदाता, पारंपरिक रूप से गैर-भाजपा दलों, जैसे सपा और बसपा की ओर झुके हुए हैं, हालांकि कुछ हद तक उनका भी विभाजन देखा गया है। [2]

जाति और धर्म का यह गठजोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई जटिलताएं पैदा करता है। जहां एक ओर, यह हाशिए पर पड़े समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर देता है और उन्हें अपनी आवाज उठाने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर, यह विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पहचान की राजनीति को बढ़ावा दे सकता है। राजनीतिक दल अक्सर इन पहचानों का उपयोग मतदाताओं को लामबंद करने और भावनात्मक अपील करने के लिए करते हैं, जिससे तर्कसंगत बहस और नीति-निर्माण के लिए कम जगह बचती है। [3]

उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल जाति और धर्म तक सीमित नहीं है। युवा मतदाता, महिला मतदाता, और आर्थिक मुद्दे भी धीरे-धीरे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। मतदाता अब केवल अपनी जातीय या धार्मिक पहचान के आधार पर ही वोट नहीं देते, बल्कि वे विकास, रोजगार, शिक्षा और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी विचार करते हैं। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई गतिशीलता आ रही है, जहां जाति और धर्म का प्रभाव बना रहेगा, लेकिन अन्य कारक भी अपनी जगह बनाएंगे। [4]

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारतीय राजनीति में बदलती संस्कृति

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म का प्रभाव गहरा और बहुआयामी है। इन्होंने राज्य की राजनीतिक दिशा को आकार दिया है और आगे भी देते रहेंगे। हालांकि, एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की जागरूकता बढ़ रही है, और वे केवल पहचान की राजनीति से परे देखने लगे हैं। भविष्य में, राज्य की राजनीति में इन दोनों कारकों का महत्व बना रहेगा, लेकिन विकास, सुशासन और समावेशी नीतियों की मांग भी उतनी ही प्रबल होती जाएगी, जो राज्य के भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है।

हिंदुत्व की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में खोजी जा सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका राजनीतिक उदय 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ हुआ। इस आंदोलन ने हिंदुत्व को एक शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण के रूप में स्थापित किया, जो हिंदू पहचान को लामबंद करने और उसे एक साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने पर केंद्रित था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस लहर को सफलतापूर्वक भुनाया, जिसने इस मुद्दे को अपनी चुनावी रणनीति के केंद्र में रखा और हिंदुत्व को राज्य की राजनीति का एक अभिन्न अंग बना दिया।

उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की अवधारणा कई आयामों से प्रकट होती है। सबसे स्पष्ट रूप से, यह मंदिरों के निर्माण और रखरखाव जैसे धार्मिक स्थलों के महत्व पर जोर देने में देखा जाता है। राम मंदिर का निर्माण इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, जिसने हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने और भाजपा के लिए एक मजबूत समर्थन आधार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह केवल धार्मिक आस्था का मामला नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक गौरव और ऐतिहासिक अन्याय के निवारण के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।

इसके अलावा, हिंदुत्व अक्सर सांस्कृतिक प्रतीकों और रीति-रिवाजों के राजनीतिकरण के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। त्योहारों का भव्य आयोजन, धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देना और यहां तक कि कुछ खाद्य आदतों पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे भी हिंदुत्ववादी एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं। ये कार्य न केवल धार्मिक पहचान को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि एक विशिष्ट

हिंदू जीवनशैली और मूल्यों को भी बढ़ावा देते हैं, जो अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों के साथ तनाव पैदा करते हैं।

"लव जिहाद" और "गोरक्षा" जैसे मुद्दे भी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीतिक अवधारणा के प्रमुख घटक बन गए हैं। इन मुद्दों को अक्सर हिंदू पहचान को खतरे में पड़ने और उसकी रक्षा करने की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह विमर्श भय और असुरक्षा की भावना पैदा करता है, जिसे राजनीतिक लाभ के लिए भुनाया जाता है, जिससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी हिंदुत्ववादी सरकारें अक्सर कठोर रुख अपनाती हैं, जिसे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के रूप में पेश किया जाता है।

हालांकि, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की अवधारणा एकरस नहीं है। इसमें विभिन्न उप-क्षेत्रीय और जातीय गतिशीलता भी शामिल है। भाजपा ने विभिन्न हिंदू जातियों को एक व्यापक हिंदुत्व के बैनर तले लाने में सफलता प्राप्त की है, जिससे पारंपरिक जाति-आधारित राजनीति को चुनौती मिली है। यह विभिन्न हिंदू समुदायों को एकीकृत करने के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का उपयोग करने की एक रणनीति है, जबकि उनकी विशिष्ट आकांक्षाओं को भी संबोधित करने का प्रयास किया जाता है।

विपक्षी दलों के लिए, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की अवधारणा एक बड़ी चुनौती पेश करती है। कई दल इसे धर्मनिरपेक्षता और समावेशी राजनीति के लिए खतरा मानते हैं। वे अक्सर सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके इसका मुकाबला करने का प्रयास करते हैं। हालांकि, हिंदुत्व की भावनात्मक अपील और इसकी गहरी सामाजिक जड़ों के कारण इसका मुकाबला करना मुश्किल साबित हुआ है। कुछ विपक्षी दल भी हिंदुत्व के नरम संस्करण को अपनाने या सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर हुए हैं ताकि वे हिंदू मतदाताओं के साथ जुड़ सकें।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में "हिंदुत्व" की अवधारणा एक शक्तिशाली और बहुआयामी बल है। इसने राज्य के राजनीतिक विमर्श, चुनावी रणनीतियों और सामाजिक गतिशीलता को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जोड़ती है। जबकि यह हिंदू समुदाय के एक बड़े हिस्से को एकजुट करने में सफल रहा है, इसने समाज में ध्रुवीकरण को भी बढ़ाया है और अल्पसंख्यकों के लिए चिंताएँ पैदा की हैं। आने वाले वर्षों में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व की भूमिका निस्संदेह राज्य के भविष्य को आकार देना जारी रखेगी, और यह देखना बाकी है कि यह सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास के लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करेगा।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारतीय राजनीति में संस्कृति एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल से गुजर रही है। पारंपरिक जाति और धर्म-आधारित पहचान अभी भी प्रासंगिक हैं, लेकिन विकास, आकांक्षा और एक मजबूत हिंदुत्व पहचान के उदय ने राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। यह बदलाव भारतीय राजनीति के लिए नई चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे यह देखा जा सकेगा कि यह बदलती सांस्कृतिक गतिशीलता राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार विकसित होती है। यह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।

संदर्भ

1. शुमिलोव ए. युवा परिवेश में चुनावी नीति के निर्माण के कारक पोलिट बुक, 2022, पृष्ठ 75-85.
2. क्रिज़्सटॉफ़ इवानेक. भारतीय पार्टी प्रतीकों की रोचक कहानियाँ. द डिप्लोमैट. 2020.
3. शौरी, अरुण. संसदीय प्रणाली: हमने इसे क्या बनाया है, हम इसे क्या बना सकते हैं. नई दिल्ली: रूपा एंड कंपनी, 2021.
4. शौरी, अरुण. शासन और उसमें आई कठोरता. नई दिल्ली: एएसए प्रकाशन, 2022.
5. रोगॉफ़ बी. मानव विकास की सांस्कृतिक प्रकृति ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, एनवाई, 2021.
6. परशुरामन एस.के. भारत में युवाओं का प्रोफ़ाइल. नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 2020.
7. जेफरी सी. टाइमपास: भारत में युवा, वर्ग और प्रतीक्षा की राजनीति। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2020.
8. अत्री वी. राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता। एस. कुमार (सं.), भारतीय युवा और चुनावी राजनीति: एक उभरती हुई भागीदारी। नई दिल्ली, 2021, पृष्ठ 1-18.
9. दास लोकतांत्रिक राजवंश: समकालीन भारतीय राजनीति में राज्य, पार्टी और परिवार। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2021, पृष्ठ 12-55